भारत : वैश्विक भागीदार *

डॉ. वाइ.वी. रेड्डी

मैं राष्ट्रपति बोलिंगर के प्रति आभारी हूं जिन्होंने मुझे लो मेमोरियल लाइब्रेरी में लब्ध प्रतिष्ठित विश्व के नेताओं के फोरम पर भागीदारी करने का निमंत्रण दिया। मुझे बताया गया है कि फोरम में भूतकाल में अद्वितीय वक्ताओं में राष्ट्रपति क्लिंटन, राष्ट्रपति पुतिन, दलाई लामा और नोबल सम्मान प्राप्त जोसेफ स्टिगलिट्ज के नाम सम्मिलित हैं। यह निमंत्रण मेरे लिए अति सम्मानीय है और मुझे उम्मीद है कि मैं परम आदरणीय डॉ. जगदीश भगवती के साथ अनौपचारिक चर्चा कर पाऊंगा।

परिचय के माध्यम से मैं वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था के साथ स्वतंत्र भारत के जुड़ाव के कुछ चयनित पक्षों की प्रस्तुति करना चाहूंगा।

यद्यपि भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र देश बना परंतु यह 26 जनवरी 1950 को लिखित संविधान को स्वीकार करने के साथ ही, जिसके द्वारा हमारे देश का शासन चल रहा है, गणतंत्र बन गया। डॉ. बी.आर.आंबेडकर, भारतीय संविधान के रचयिता, को कोलंबिया विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के अवसर का लाभ मिला और उन्होंने यहीं से पीएच.डी. हासिल की। समानता और सामाजिक न्याय के डॉ. आंबेडकर के कई विचार प्रो.जॉन ड्वे से प्रेरित थे। प्रो.एडविन सेलिगमैन, जो भारत के ऐतिहासिक स्वातंत्र्य वीर लाला लाजपत राय के मित्र थे, युवा अंबेडकर के मेंटर बने। डॉ. अंबेडकर लंदन में अपने अनुसंधान और शिक्षा से लाभान्वित हुए। ये कुछ उदाहरण इस बात के हैं कि कैसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और भारत के संविधान, जिसके द्वारा हम आज शासित होते हैं, को वैश्विक स्कॉलरशिप से आम तौर पर और कोलंबिया विश्वविद्यालय और अमरीका से खासतौर पर साझेदारी के लाभ प्राप्त हुए। प्रसंगवश कोलंबिया विश्वविद्यालय ने हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल

* डॉ.वाइ.वी.रेड्डी, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क में विश्व नेताओं के फोरम में 15 अप्रैल 2008 को की गई परिचयात्मक टिप्पणी ।

नेहरू को स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद अमरीका का पहला दौरा करने पर उन्हें ऑनरेरी डिग्री से सम्मानित किया था।

वैश्विक समाज की एक प्रमुख चारित्रिक विशेषता है जातियों, धर्मों, संस्कृतियों, विचारधाराओं और भाषाओं में विविधता। भारत को अपने आप में वैश्विक समाज की तमाम भिन्नताएं समेटे रखने का वैशिष्ट्य प्राप्त है। उदाहरण के तौर पर जोरोस्ट्रिअनिज्म को अपनानेवाले तमाम लोगों - जिन्हें पारसी नाम से भी जाना जाता है - के लिए भारत उनका घर है। भारत के दो राज्य कम्युनिस्ट शासित हैं। वस्तुतः हमारा देश एक अद्वितीय संघ है जहां संविधान के प्रावधानों के भीतर ही रहते हुए भावनाओं का सम्मान करते हुए विद्यमान राज्यों में से काटकर नए राज्य निर्मित किए गए। हमारे देश में कई राष्ट्रीय भाषाएं हैं जिनमें सरकार का कार्य संचालित किया जाता है। भारत में प्रत्येक करेंसी नोट, जो आप देखते हैं, पर मूल्यवर्ग को अलग-अलग लिपि में 17 भाषाओं में लिखा गया है। संक्षेप में स्वतंत्र भारत बातचीत में और विविधता भरे पहचानवाले लोगों का निभाव करने और उन्हें स्वीकार करने में दृढ़ विश्वास रखता है।

ये चारित्रिक विशेषताएं भारतीयों और भारतीय कंपनियों को अन्य राष्ट्रीयताओं के साथ रहने और सद्भावपूर्ण व्यवहार करने में सक्षम बनाती है।

अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र के तौर पर सुप्रतिष्ठित है। विशेष तौर पर स्वतंत्रता के बाद का भारत शेष विश्व को दिए गए अपनी मौद्रिक जबाबदेही से कभी पीछे नहीं हटा और न ही कभी इसने अपने भुगतान दायित्वों की सुस्पष्ट रीशेड्यूलिंग की मांग की है। 1991 में हमारे देश में करेंसी का चलनिधि संकट पैदा हुआ था जो मुख्यतया ईराक युद्ध और सोवियत रूस के साथ व्यापार खत्म होने के कारण था परंतु हमने सोने को गिरवी रखने का फैसला किया, आयातों को अत्यधिक कम किया और आइएमएफ तथा विश्व बैंक की सहायता से सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ की। इस संकट और समायोजन के संपूर्ण भार का वहन हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था के द्वारा सफलतापूर्वक किया गया।

वर्तमान वित्तीय उथल-पुथल और मैक्रो असंतुलन के संभावित प्रसार के दौर में भारत ने हाल के अधिकांश वर्षों में चालू खाता घाटे को जीडीपी के लगभग 1 प्रतिशत[1] पर रखते हुए तथा बाजार आधारित विनिमय दर को स्थिर रहते हुए स्थायित्व कायम रखने की भूमिका अदा की है। वैश्विक मैक्रो आर्थिक असंतुलन में भारत का कोई योगदान नहीं रहा है तथापि निकट भविष्य में इससे जुड़े मुद्दों को हल कैसे किया जाता है, उसमें भारत का हित भी जुड़ा है।

वर्तमान में, संप्रभुतासंपन्न धन निधि (एसडब्ल्यूएफ) की भूमिका पर बहस जारी है। भारत इनमें से कई देशों से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निवेश की प्राप्ति कर रहा है अतः चल रही बहस में भारत का भी हित है। इस भूमिका में भारत में विदेशी मुद्रा रिज़र्व लगभग 300 बिलियन अमरीकी डॉलर है जिसका प्रबंधन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विश्व के अन्य सभी केन्द्रीय बैंकों पर लागू अधिदेशों की तर्ज़ पर और आइएमएफ के दिशानिदेशों के अनुरूप किया जाता रहा है। तथापि अपने वाणिज्यिक निर्णयों के आधार पर भारतीय कंपनियां निवेश करने का इरादा करती हैं और अन्य देशों में अन्य उद्यमों का विलयन अथवा अधिग्रहण करती हैं। भारतीय कंपनियों के द्वारा बाजार आधारित इस प्रकार की पहलकदमियों के लिए सरकारी नीति कोई प्रोत्साहन नहीं देती और न ही उन्हें हतोत्साहित करती है।

[1] 2004-05 में 0.4 प्रतिशत, 2005-06 में 1.2 प्रतिशत और 2006-07 में 1.1 प्रतिशत।

1991 से प्रारंभ सुधारों से अब तक भारत के बाह्य क्षेत्र ने काफी शक्ति और मजबूती दिखाई है जो तमाम घरेलू और वैश्विक राजनीतिक घटनाचक्रों और खाद्य तथा तेल आपूर्ति आघातों के बावजूद बरकरार रही है। जीडीपी के प्रतिशत के तौर पर वस्तुओं और सेवाओं में भारत का बाह्य व्यापार अमरीका के बाह्य व्यापार की तुलना में अधिक (क्रमशः 48 प्रतिशत और 29 प्रतिशत पर) है और एक प्रकार से वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भारत के व्यापार एकीकरण को दर्शाता है। भारत में चालू खाता की पूर्ण परिवर्तनीयता कर दी गई है परंतु हमारी अपेक्षा निर्यात आय का प्रत्यावर्तन और समर्पण करने की भी है ताकि चालू खाते की आड़ में पूंजी खाते में लेनदेन न किया जा सके। पूंजी खाता अनिवासी भारतीयों, सुनियंत्रित वित्तीय संस्थाओं और कंपनियों के लिए लगभग पूरी तरह खुला है। निवासी भारतीयों के संदर्भ में पूंजी खाता निवासी कंपनियों के लिए पूरी तरह खुला है तथा व्यक्तियों और वित्तीय मध्यस्थों के लिए आंशिक रूप से खुला है। संक्षेप में, हम व्यापार और चालू खाता के मामले में वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ पूर्णतया जुड़ गए हैं और भू-संपदा, राजकोष और वित्तीय क्षेत्रों में सुधार की बढ़ती हुई गति के साथ कदमताल करते हुए पूंजी खाता उदारीकरण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

वित्तीय बाजारों और संस्थाओं - विशेष तौर पर अमरीका स्थित - में हो रही उथल-पुथल ने संभावित संक्रमण के बारे में प्रश्न पैदा कर दिए हैं। मुद्रा, सरकारी प्रतिभूतियां और विदेशी मुद्रा बाजार भारत में स्थिर रहे हैं और हमारे दृष्टिकोण से उन पर प्रत्यक्ष और प्रथम दौर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तथापि भारतीय इक्विटी बाजार जो आमतौर पर वैश्विक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, हाल के महीनों में वोलेटाइल रहा और इसका कुछ असर परिवर्तनशील रुख पर पड़ा। हमारे देश में बैंक -प्रधान वित्तीय क्षेत्र है और बैंकों के पास सशक्त पूंजी आधार मौजूद है।

वैश्विक गतिविधियों और भारत में मुद्रा आपूर्ति, ऋण और आस्ति कीमतों में तीव्र वृद्धि पर ध्यान देते हुए हमने 2004 से बैंकों के संदर्भ में जोखिम भार और प्रावधानीकरण की अपेक्षाओं में वृद्धि की है तथा कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में एक्सपोज़र सीमाओं को कम किया है अथवा सुसंगत किया है। इन उपायों के साथ-साथ तुलनपत्र-बाह्य मदों और बैंकों तथा गैर-बैंक वित्तीय कंपनियों के बीच संबंधों से संबंधित विवेकपूर्ण विनिर्देशों को भी लागू किया गया। कई सुरक्षा उपाय विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों और रिपो बाजार तक पहुंच देने के संदर्भ में निर्मित किए गए, ताकि बैंकों को चलनिधि से जुड़ी समस्याओं के विरुद्ध सुरक्षित किया जा सके। इन सबसे महत्वपूर्ण है 2004 में मौद्रिक निभाव को वापस लिया जाना और ओवरहीटिंग के आरंभिक संकेतों के प्रति संवेदनशील रहते हुए उसे क्रमिक रूप से सुसंगत किया जाना, जबकि अन्य संबंधित विवेकपूर्ण उपाय आस्तियों में जोखिम के प्रति बैंकों के एक्सपोज़र की समस्या का समाधान करते थे। अतः हमारे मूल्यांकन के अनुसार जहां तक प्रथम दौर अथवा प्रत्यक्ष प्रभावों का प्रश्न है, भारतीय वित्तीय क्षेत्र अधिकतर अन्य ईएमई की तुलना में संक्रमण से कम प्रभावित हो सकता है।

भारतीय वास्तविक अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में दो शब्द कहना यहां जरूरी है। से वास्तविक जीडीपी की वार्षिक वृद्धि 2003-04[2] से औसतन 8.7 प्रतिशत रही है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में निवेश और बचत 2004-05[3] से 30 प्रतिशत से अधिक रहा है जो

[2] 2003-04 से 2007-08
[3] 2004-05 से 2006-07

मध्यावधि के दौरान उत्पादन और उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की संभावना को दर्शाता है। इसी प्रकार विश्व के अधिकांश देशों की तरह आमतौर पर भारत को भी 2004-05[4] से अल्प मुद्रास्फीतिकारी परिस्थितियों, जिसका औसत लगभग 5.2 प्रतिशत रहा था,से होकर गुजरना पड़ा । तथापि हाल ही की वैश्विक गतिविधियों के कारण (खाद्यान्न, ईंधन और धातु की कीमतों तथा वित्तीय बाजारों में उथल-पुथल के संदर्भ में) घरेलू उत्पादन और कीमतें दोनों ही कुछ दबाव में रहीं।

हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं वे हैं - गरीबी उन्मूलन, जल का सक्षम उपयोग, कृषि में पुनःवृद्धि हासिल करना, भौतिक और सामाजिक आधारभूत संरचना में सुधार करना, मानव कौशल का उन्नयन करना और जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वह है वास्तविक क्षेत्र में लचीलापन बढ़ाने के साथ राजकोषीय सशक्तीकरण । हमारी शक्तियां मुख्यतया जनसंख्या लाभांश, राजनीतिक प्रणाली के स्थायित्व और व्यापक आधार वाले एवं बढ़ रहे उद्यमी वर्ग (जिसमें नवोन्मेषीकरण के प्रति इच्छाशक्ति है) के उदय में निहित हैं। इन चुनौतियों से पार पाने और शक्तियों का लाभ प्राप्त करने में वैश्विक अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से अमरीका, के साथ हमारा जुड़ाव एक बहुत ही प्रमुख भूमिका अदा करेगा।

हम वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ निरंतर परस्पर लाभकारी व्यवस्था के चलते रहने के प्रति आशावान हैं । विश्व के कई भागों - यूएसए, मिडिल ईस्ट, यूके और पूर्वी एशिया में भारतीय अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनकी सेवाएं एक ओर अल्प कौशल से लेकर दूसरी ओर उच्च कौशल के धनी प्रोफेशनल तक के रूप में उपलब्ध हो रही हैं। विप्रेषण के रूप में उनका वार्षिक योगदान अब जीडीपी का लगभग 3 प्रतिशत है। यह योगदान निर्यात सेवाओं, विशेष रूप से सॉफ्टवेयर जिसका योगदान भी लगभग इतना ही है, के अलावा है। यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, चीन इत्यादि देशों में उच्च शिक्षा के विश्व विद्यालयों में विदेशी छात्रों में भारतीयों की सर्वाधिक उल्लेखनीय उपस्थिति।

भारत में उच्च वृद्धि दर कायम रहने के परिणामस्वरूप कौशल पलायन की विपरीत धारा भी बहनी प्रारंभ हुई है अर्थात भारत में अधिक लाभकारी अवसरों को पाने के लिए विदेशी राष्ट्रिक और प्रवासी भारतीय यहाँ के उद्यमों में रुचि प्रकट कर हैं। इसके फलस्वरूप तदनुरूप व्यापार और निजी कारोबारी संपर्क सूत्रों में भी वृद्धि दर्ज हो रही है। उदाहरणार्थ हाल ही में वैश्विक स्तर पर सक्रिय एक बैंक ने भारत में '' प्रवासी खाता '' नाम से एक उत्पाद प्रारंभ किया है । इस खाते के माध्यम से भारत में तेजी से बढ़ रहे प्रवासी समुदाय को मूल्यवर्धित सेवाएं उपलब्ध होंगी।

वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ यह व्यवस्था परिपक्व होकर एक स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया बन गयी है और इस प्रक्रिया से होने वाले लाभ कई लोगों को मिल रहे हैं और भारत में अधिकांश लोगों तक उसके लाभ पहुंच रहे हैं।

सामाजिक, राजनीतिक और वित्तीय प्रणालियों के संबंध में भारत में जो विभिन्नता पाई जाती है उसको ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक नीति के विषय की मांग है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भारत के एकीकरण का प्रबंधन आपसी भागीदारी और परामर्शकारी विधि से और क्रमिक रूप से किया जाए।

[4] 2004-05 से 2007-08 (22 मार्च 2008 को समाप्त सप्ताह तक)